

THE NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED,  
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)  
“N.S.I.C. BHAWAN”  
OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, NEW DELHI-110020

**NSIC**

ISO 9001:2008

SIC/HO/RTI/CPIO(27)/2015-16

60M

Dated: 27/08/2015

श्री प्रवीण राए,  
बी-7, प्रथम तल, विभूति खंड,  
गोमती नगर,  
लखनऊ

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु 1

कृपया अपने आवेदन दिनांक 31/07/2015 (प्राप्ति दिनांक 03/08/2015) का सन्दर्भ ग्रहण करें आपने अपने इस आवेदन में निम्नलिखित के संबंध में सूचना प्रदान करने का अनुरोध किया है।

- (1) आवेदक को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा प्रमाण पत्र संख्या NSIC/GP/KAN/201410008834 जारी किया गया है।
- (2) प्रार्थी ने प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर सर्विस सेक्टर में कई विभागों में कार्य हेतु आवेदन किया था जिसको संबंधित विभागों ने निरस्त कर दिया।
- (3) अतः आपसे अनुरोध है कि सर्विस सेक्टर में हमारी सहभागिता किस प्रकार से होगी तथा क्या लाभ प्राप्त होंगे, विस्तृत जानकारी प्रदान करने की कृपा करें।

मांगी गई सूचना का उत्तर जैसा कि एन एस आई सी के सम्बंधित विभाग द्वारा प्रदान किया गया है नीचे दिया जा रहा है :-

भारत सरकार, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 26/03/2012 की राजपत्र अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित किया है कि "पब्लिक प्रोक्योर्मेंट फॉर माइक्रो एंड स्माल इंटरप्राइजेज (एम एस ई) आदेश 2012" (प्रतिलिपि संलग्न) 01 अप्रैल 2012 से प्रभावी है। इस उपरोक्त अधिसूचना में यह कहा गया है कि एन एस आई सी के साथ पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयां निम्न लाभ पाने की पात्र हैं:-

1. टेंडर निःशुल्क मिलते हैं।
2. बयाना जमा राशि के भुगतान से छूट (ई एम ई)

3. टैंडर में एल - 1 + 15 के मूल्य बैंड में उद्धत कर करने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को कुल टैंडर वैल्यू का 20% तक आपेक्षित भाग की सप्ताहाई करने की भी रविधा रहती है। लेकिन उसे अपनी दरे पर एवं पर रही गैर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम यूनिट की दर तक कम करने पर ही यह सुविधा मिलती है।
4. 358 वस्तुएं सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों से अनिवार्य रूप से खरीदे जाने के लिए आरक्षित की गई हैं।

इसके अलावा उपरोक्त आटेश को अनुसार प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय या इसके विभाग अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए जरूरी हो गया है कि वे अपने वार्षिक खरीद के लक्ष्य में कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% तक की खरीद सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाईयों से ही करें और यह आटेश 01 अप्रैल 2015 से आवश्यक हो गए हैं। इस आटेश ने अहम उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोन्नत करना और उनके विकास करने में सहायता करना है ताकि वे और अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकें।

उपरोक्त के आलोक में सम्बंधित यूनिट सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एम एस एम ई) आटेश 2012 की प्रोक्योरमेंट पालिसी के अर्थों में एल एस आई के साथ पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को चाहिए कि वे अनुमत लाभों के लिए यह मुददा सम्बंधित विभाग को प्रस्तुत करें।

यदि आप हमारे उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो कृपया निम्नलिखित अपीलीय अधिकारी को इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं:-

पी. उदयाकुमार,  
निदेशक (पी एंड एम),  
अपीलीय अधिकारी,  
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड,  
“एन एस आई सी भवन”,  
ओखला औद्योगिक क्षेत्र,  
नई दिल्ली -110020.



(ए. के. मितल )  
री पी आई ओ

संलग्न : इति उपरोक्त

